सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-645
30/12/2017

मजबूत इरादे एवं दृढ़ संकल्प की बदौलत सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है :– मुख्यमंत्री

पटना, 30 दिसम्बर 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के कोशियावां पंचायत स्थित चमेरा गाँव में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने 69865 लाख रूपये की 114 योजनाओं का शिलान्यास एवं 97 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 132 योजनाओं का लोकार्पण जनसभा स्थल मंच से किया। चमेरा गाँव भ्रमण के दौरान आदर्श ग्राम चमेरा सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय का रिबन काटकर उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। मध्य विद्यालय हिलसा की छात्राओं ने बाल विवाह उन्मूलन को लेकर नाटक प्रस्तुत करने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने में अपना भरपूर योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रामवासी मधुकर जी के घर के अंदर प्रवेश कर मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभुक रुक्मिणी देवी के निर्मित मकान का भी अवलोकन किया। ग्रामीणों द्वारा उत्पादित मशरूम के लगे स्टॉल और किसान पाठशाला का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। मध्य विद्यालय ओरियावां, बादराबाद प्रांगण में महिला विकास निगम, नाबार्ड और जीविका द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाने वाले दीपक कुमार और मुकेश कुमार को मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट प्रदान किया। अंतर्जातीय विवाह करने वाली श्रीमती विजेता को एक लाख रुपये का चेक प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री ने भेंट किया। चमेरा गाँव भ्रमण के दौरान जगह–जगह फूलों का छिड़काव और स्वागत गान गाकर महिलाओं ने जबकि बालिकाओं ने रंगोली बनाकर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। जनसभा स्थल मंच पर विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पुष्प–गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए आप को हृदय से धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा कई जिलों में करने के बाद हम आपके बीच पहुंचे हैं और आज ही नवादा में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में हम भ्रमण करने पहुंचे थे, जहां काफी कुहासा और ठंड के बाद भी भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का काम तेजी से चल रहा है और हम न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है हर इलाके और हर तबके का विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, पुल–पुलिया निर्माण का मामला हो, कृषि का विकास हो, सिंचाई सुविधा हो, तमाम विकास के काम किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 में पहला कृषि रोड मैप बनाकर उसका अनुपालन शुरू किया गया, उसके बाद दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 2017 बनाया गया और अब तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2022 बनाया गया है, जिसकी शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि हम जो कृषि रोड मैप बनाते हैं, उसका मकसद होता है कृषि विकास

के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं, उसको मुहैया कराना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध पर भी काफी नियंत्रण हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा विवाद अगर बिहार में किसी चीज को लेकर है तो वह है भूमि विवाद। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया और इसके लिए हर अनुमंडल, प्रत्येक जिले के साथ ही सभी विभागों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल 5 जून से इसकी शुरुआत हुई है और अब तक दो लाख से भी अधिक शिकायतों का निपटारा इस कानून के जरिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर माह में निश्चय यात्रा पर हम निकले थे और शिकायत केंद्रों पर जाकर किस तरह से वहां पर कामों का निपटारा हो रहा है, उसको मैंने देखा और इस क्रम में 17–18 शिकायत केंद्रों का मैंने भ्रमण भी किया। अब इसमें नई तकनीक लगा कर उसमें और सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले होता था, जिसमें पहले सोमवार को भूमि विवाद, अपराध और पुलिस से जुड़े मामले पर सुनवाई होती थी, उसमें सबसे ज्यादा भूमि विवाद से जुड़े मामले देखने को मिलते थे। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद निराकरण के लिए भी कानून बनाया गया और अब लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भी भूमि विवाद का निपटारा तेजी से हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने कृषि रोड मैप की शुरुआत की और ऐसे में भूमि विवाद का निपटारा अगर हो जाए तो यह काफी सहायक सिद्ध होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद निपटारे के लिए पूरे बिहार में नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम शुरु हुआ है क्योंकि सौ साल पहले सर्वे हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जा रहा है और 39 अंचल में ऑनलाइन दाखिल खारिज की अब तक व्यवस्था भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पहले गांव से बाजार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण बाजार के अभाव में व्यापारी ओने पौने दामों में किसानों के द्वारा पैदा किए गए अनाज और सब्जी खरीद लिया करते थे। उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत अब सभी गांवों और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है और इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक–एक गांव और बसावट को हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांशतः टोलों में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं और वैशाख महीने में भी गांव में कीचड़ हुआ करता था, जिसको देखते हुए सात निश्चय योजना के तहत गली और नाली का पक्कीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी का ख्वाब, इच्छा और उसकी अपेक्षा होती है कि उन्हें शौचालय, नल का जल, पक्की गली और नाली, बिजली की उपलब्धता जैसी अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित पेयजल स्रोत हैं, वहां लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी पी0एच0ई0डी0 विभाग को दी गई है, जो विकेंद्रीकृत तरीके से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता लोगों को कराएगा। जिन इलाकों में गुणवत्ता प्रभावित जलस्रोत की समस्या नहीं है, वहां पंचायतों के माध्यम से वार्ड वाइज काम किया जा रहा है ताकि हर घर नल का स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और जो कुछ टोलें बचे हैं, उसमें अप्रैल 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है इच्छुक परिवार तक बिजली पहुंचाना और एक साल के अंदर हर इच्छुक परिवार को हम बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में कई काम हुए हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसके बाद अब तक तीन चुनाव भी हो चुके हैं। पुलिस की नौकरी में

35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया, जो देश में सबसे सबसे ज्यादा है। बालिकाओं को पोशाक योजना और साइकिल योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि आठ लाख सहायता समूह बिहार में बन गया है और हमारा लक्ष्य दस लाख तक इसे ले जाना है, उस दिशा में काम भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में समीक्षा यात्रा के क्रम में हम जा रहे हैं, वहां महिला पुलिस के माध्यम से सलामी दी जा रही है, यह मामूली बात नही है क्योंकि पहले गिनी चुनी महिला पुलिस ही हुआ करती थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हर प्रकार की सेवा में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है, ऐसे में जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें चार लाख रुपये तक की ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के ढुल–मूल रवैये के कारण स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ जितनी तेजी से अधिक से अधिक बच्चों तक सरकार पहुंचाना चाहती है, वह नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के बाद राज्य सरकार अपना वित्तीय कारपोरेशन बनाकर बच्चों को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा हासिल करने में हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 13.9 है जिसे बढ़ाकर हम 30 प्रतिशत से भी आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं को 2 साल तक स्वयं सहायता भत्ता के साथ–साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल की 240 घंटे की ट्रेनिंग प्रत्येक ब्लॉक में दी जा रही है ताकि युवा सशक्त हो सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं के उद्यमिता के लिए वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जी0एन0एम0 इंस्टीच्यूट, महिला आई0टी0आई0, जबकि प्रत्येक सब डिवीजन में ए0एन0एम0 स्कूल और आई0टी0आई0 की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था रहेगी ताकि पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशनगंज जैसे बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से पहले जहां 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अब उसे हासिल कर लेने के बाद उस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे का कर दिया गया है और इसके लिए तेजी से सड़क, पुल–पुलिया निर्माण का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बड़े विकास के काम तीव्र गति से हो रहे हैं और औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई, जिसके बाद अब हर परिवार और पूरे बिहार में अमन–चैन कायम हुआ है। परिवारों में खुशहाली लौटी है और जो शराब सेवन में लोग पैसे खर्च कर दिया करते थे, उन पैसों का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में, उनके पहनावे में और घर खर्च में किया जा रहा है। इससे लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे दो नंबरी धंधेबाज हैं जो अवैध शराब के काम में सरकारी तंत्र को घूस देकर जुटे हुए हैं, जिन पर नकेल कसना आवश्यक है। लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खास तौर पर युवाओं और महिलाओं को इसके लिए सजग होना होगा ताकि दो नंबर धंधेबाजों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए नया तंत्र भी विकसित किया जा रहा है और जो भी बिजली के ट्रांसफार्मर गांव में लगे हुए हैं, उन पर बोर्ड लगाया जा रहा है, जिस पर टेलीफोन नंबर होगा जिसके माध्यम से अवैध शराब के कारोबार करने वाले या शराब का सेवन करने वालों की सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से हो रही है और ऐसे में 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 6.5 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन लोगों के पास हैं, जिसके माध्यम से लोग आसानी से सूचना दे सकते हैं और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है और सूचना दिए जाने पर क्या कार्रवाई की गई इसकी भी समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जागृति के बिना इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। वैशाली और रोहतास में जहरीली शराब से हुई मौत की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली में तीन और रोहतास में चार लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई, ऐसे में इन घटनाओं का उदाहरण देते हुए आप उन लोगों को समझाइए, जो लोग आज भी अवैध शराब के काम में जुटे लोगों से शराब लेकर पी रहे हैं। उन्हें समझाइए कि अगर वह ऐसा करते हैं तो अपनी जान गवा देंगे। लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको हर पल सतर्क होना होगा कि कहीं लोग शराब छोड़कर कोई दूसरी नशीली चीज का इस्तेमाल नहीं करने लगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून लागू होने के बाद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें लोग अपने सुझाव आकर देते हैं और ऐसे में एक महिला लोक संवाद में आई, जिसने कहा कि आप ने शराबबंदी करके बहुत अच्छा कदम उठाया लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ भी सशक्त अभियान चलना चाहिए। तब हमलोगों ने तैयारी की और दहेज प्रथा के साथ बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाने का फैसला किया क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कानूनन अपराध है लेकिन इसके बावजूद भी बाल विवाह होते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि कम उम्र में महिलाएं गर्भधारण करती हैं तो या तो वे मौत की शिकार हो जाती हैं या उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वे मंदबुद्धि या बौनेपन के शिकार होते हैं, साथ ही कई बीमारियों से भी जूझते हुए पाए जाते हैं। इससे उबरना होगा और समाज से दहेज प्रथा को भी खत्म करना होगा। लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक संकल्प ले लें कि दहेज लेने वाले की शादी समारोह में आप शामिल नहीं होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि समाज से दहेज प्रथा चंद वर्षों में खत्म हो जाएगी। इसमें अपवाद मत रखिएगा कि गोतिया–रिश्तेदार के यहां शादी है तो दहेज लेने देन के बाद भी शादी समारोह में शरीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम तो स्पष्ट तौर पर कह दिए हैं कि शादी कार्ड पर लिखना होगा कि बिना दहेज लेन–देन शादी कर रहे हैं, तब ही हम उस शादी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान की शुरुआत हुई। अब इस अभियान को मूर्तरुप देने के लिए हमलोगों ने यह तय किया है कि 21 जनवरी 2017 को जिस तरह से शराबबंदी और नशामुक्ति के पक्ष में चार करोड़ लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराकर एक बड़ा संदेश दिया था और अपनी भावना का प्रकटीकरण किया था, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर शराबबंदी, नशामुक्ति के साथ–साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला 21 जनवरी 2018 को बनेगी। जनसभा में मौजूद लोगों को हाथ उठाकर संकल्प दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम का समय है और ऐसे में आप हाथ उठाकर सूर्य भगवान के समक्ष संकल्प लिए हैं इसलिए भूलिएगा नहीं और 21 जनवरी को रविवार का दिन है, ऐसे में आप मन बना लीजिए कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि जबर्दस्त मानव श्रृंखला बने। आपके मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प की बदौलत समाज से इन कुरीतियों को समाप्त किया जा सकेगा। मानव श्रृंखला में शामिल होने के आह्वान के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं। सभा के अंत में जिलाधिकारी श्री त्यागराजन एस0एम0 ने मुख्यमंत्री को तेलहाड़ा विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न भेंट किया।

जनसभा को ग्रामीण कार्य मंत्री सह नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद श्री कौशलेन्द्र कुमार, विधायक श्री हरिनारायण सिंह, विधायक श्री रवि ज्योति, विधान

पार्षद श्रीमती रीना यादव, विधान पार्षद श्री हीरा प्रसाद बिंद, पूर्व विधान पार्षद श्री राजू यादव, पूर्व विधायक ई0 सुनील कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राम सागर सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष श्री राजू पासवान, रालोसपा जिला अध्यक्ष भरत प्रसाद, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री अरविंद कुमार, सचिव ग्रामीण कार्य एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव एवं नालंदा जिले के प्रभारी पदाधिकारी श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना आई0जी0 श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार पुरिका सहित अन्य कई वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।

******